www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 05 | जौनपुर, मंगलवार, 18 अगस्त 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह एक हाई–पावर कमेटी बनाना चाहता है। इस कमेटी में पूर्व जज और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। यह कमेटी दिल्ली में छम्म्ज पेपर लीक को लेकर 20 जुलाई को हुए छात्र विरोध–प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की ज्यादतियों और हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्णायक जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तब कही जब वह 20 जुलाई के प्रदर्शनों के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ताओं ने इस घटना की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। इनमें से एक याचिका में खास तौर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन के कथित इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया है। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि कमिटी मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी, जिसमें पुलिस की बर्बरता के आरोप, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बर्ताव और प्रदर्शनों के दौरान बल का इस्तेमाल शामिल है। बेंच ने यह भी साफ किया कि जांच सिर्फ किसी एक पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये बातें तब सामने आईं जब एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया।

फांसी की जगह मौत का इंजेक्शन देने की मांग खारिज

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मृत्युदंड देने के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने फांसी की जगह कथित तौर पर कम पीड़ादायक विकल्प, जैसे लीथल इंजेक्शन, अपनाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि फिलहाल भारत में फांसी के जरिए मृत्युदंड देने की मौजूदा कानूनी व्यवस्था लागू रहेगी। याचिका में फांसी की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे अधिक मानवीय विकल्प से बदलने की मांग की गई थी। हालांकि, अदालत ने इस मामले से जुड़े पुराने फैसलों को बड़ी पीठ के पास भेजने की मांग को भी स्वीकार नहीं किया।सीनियर अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा की ओर से दायर जनहित याचिका में दंड प्रक्रिया संहिता की पुरानी धारा 354(5), जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 393(5) के रूप में लागू किया गया है, की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि फांसी का तरीका अत्यधिक पीड़ादायक और अमानवीय हो सकता है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का हवाला देते हुए।

मनुष्य को सदैव आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मंगलवार को सुभाषित शेयर किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक श्लोक, "उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो ह्येव पौरुषम। अप्यपर्वणि भज्येत न नमत्वेव कस्यचित्ए" साझा किया है। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि मनुष्य को सदैव आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए। सच्चा पुरुषार्थ और पराक्रम इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे, बल्कि सत्य, धैर्य और आत्मगौरव के साथ अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। बीते दिन सोमवार को प्रधानमंत्री की ओर से सुभाषित शेयर करते हुए लिखा गया था, "सामूहिक संकल्प और एकता की

शक्ति से ही देश आगे बढ़ता है। यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है।" उन्होंने एक श्लोक, "समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासतिए" भी साझा किया था, जिसका हिंदी अर्थ है कि हम सबके संकल्प एक समान होने चाहिए, हमारे मन एकता के भाव से जुड़े होने चाहिए, जिससे हम सभी परस्पर सहयोग तथा समान व्यवहार के साथ समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इससे पहले प्रधानमंत्री की ओर से सोशल मीडिया पर 14 अगस्त को सुभाषित शेयर किया गया था। तब उन्होंने लिखा था, "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी देशवासियों का हृदय से नमन, जिन्होंने उस वीभत्स दौर से निकलकर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने साहस और सामर्थ्य से दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संकल्पों को सिद्ध किया जाता है। आइए, सद्भावना और एकजुटता की राष्ट्रीय भावना को और सशक्त करें।" पीएम ने एक श्लोक, "उद्यमस्य प्रसादेन दृश्यन्ते विविधाः कलाः। कातरा एव जल्पन्ति यद् भाव्यं तद् भविष्यतिए" भी साझा किया था, जिसका हिंदी अर्थ है कि परिश्रम, उद्यम और पुरुषार्थ से ही विविध कलाएं, विज्ञान, तकनीकी कौशल, शिल्प तथा नवाचार विकसित होते हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए, मनुष्य को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए।

बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों को राज्य वापसी का दिया भरोसा

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को रोजगार के अवसर पैदा करने और बड़े औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देकर राज्य के प्रवासी श्रमिकों की धीरे–धीरे वापसी सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने आदिवासी बहुल पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर में 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ग्रीनफील्ड एकीकृत स्टील प्लांट के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, ष्मैं पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को भरोसा देता हूं कि उन्हें राज्य में वापस आने का अवसर मिलेगा। रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। हमारे पास बड़े औद्योगीकरण की योजनाएं हैं। रघुनाथपुर का यह स्टील प्लांट करीब 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देगा। इलाके के स्थानीय आदिवासी युवाओं को भी नौकरी मिलेगी। इससे पूरे क्षेत्र का विकास होगा।ष मुख्यमंत्री ने पिछले महीने इसके शिलान्यास की प्रक्रिया शुरू की थी। हाल ही में बांकुरा जिले के मेजिया में 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाले एकीकृत स्टील प्लांट का उद्घाटन भी किया गया था। उन्होंने सोमवार को पुरुलिया के मानबाजार में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) की सहायता से तैयार पेयजल पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि इस्कॉन जल्द ही पुरुलिया जिले के सभी सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था शुरू करेगी।

पीएम आवास योजना को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजस्थान के बारां में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में 2,89,355 पक्के मकानों के निर्माण के लिए 3,473 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। साथ ही कृषि उन्नति और पीएम आरकेवीवाई के लिए 340.59 करोड़ रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र भी दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राजस्थान में 29,13,749 नए संभावित लाभार्थियों का सर्वे किया गया है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद पात्र पाए जाने वाले लोगों को भी आवास आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने जिला और पंचायत स्तर पर पारदर्शी तरीके से सूची प्रदर्शित करने, आपत्तियां सुनने और पात्र लोगों के नाम गलत तरीके से सूची से हटाए जाने से रोकने के निर्देश

दिए। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत पात्रता नियमों में तीन महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी दी। अब दोपहिया वाहन रखने वाले परिवार भी पक्के मकान के लिए पात्र हो सकेंगे। वहीं, जिन परिवारों में महिला की मासिक आय 15,000 रुपए तक है, उन्हें भी योजना का लाभ मिल सकेगा। पहले आय सीमा 10,000 रुपए प्रति माह थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख और लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर बहुत–बहुत शुभकामनाएं। उनका सुधारों और आर्थिक विकास पर जोर है, जिससे वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की हमारी कोशिशों को गति दे रही हैं। ईश्वर उन्हें लंबी और स्वस्थ आयु प्रदान करें।" लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने

एक्स पर पोस्ट किया, "वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुख और लंबी आयु प्रदान करे।" राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पोस्ट में कहा, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! आपके कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच एवं राष्ट्रहित में लिए गए प्रभावी निर्णय भारत की आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भरता को नई गति प्रदान कर रहे हैं। प्रभु श्रीराम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं।" हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक्स पर पोस्ट किया, "केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और विकास को गति देने में आपका समर्पित कार्य सराहनीय है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं।" उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट में कहा, "भाजपा की वरिष्ठ सदस्य केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपको यशस्वी, सुदीर्घ एवं आरोग्यमय जीवन की प्राप्ति हो, देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है।

आंध्र प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ- चंद्रबाबू नायडू

अमरावती, (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को स्पष्ट किया कि शिक्षकों की भर्ती के लिए श्मेगा डीएससीश में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने विधानसभा में मेगा डीएससी भर्तियों पर बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर शहिट–एंड–रनश की राजनीति के जरिए झूठा अभियान चलाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 से 2024 के बीच सत्ता में रहने वालों ने एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की, लेकिन शिक्षा क्षेत्र के बारे में बड़े–बड़े दावे किए। उन्होंने

कहा कि अब तक हुई 14 डीएससी परीक्षाओं में से 11 परीक्षाएं टीडीपी और एनडीए सरकारों के दौरान आयोजित की गईं और शिक्षकों की भर्ती की गई। इन भर्तियों में भ्रष्टाचार की एक भी शिकायत नहीं मिली है। सीएम ने कहा, षपिछली सरकार ने पांच साल में एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की। पद संभालने के तुरंत बाद अपने पहले ही हस्ताक्षर से हमने मेगा डीएससी के जरिए 15,941 शिक्षकों के पद भरे। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई और नियुक्तियां सिर्फ 148 दिनों के भीतर कर दी गईं।ष उन्होंने बताया कि टीईटी और डीएससी नोटिफिकेशन के साथ–साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन (क्षैतिज और लंबवत आरक्षण) प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू किया गया। उन्होंने कहा, ष्हमने 13 विषयों में 42,000 सवाल चुने और सबसे अच्छे उपलब्ध तरीके से परीक्षा आयोजित की। परीक्षा 154 केंद्रों पर कंप्यूटर–बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की गई और नतीजे भी पारदर्शी तरीके से जारी किए गए। पूरी तरह से मेरिट के आधार पर 15,941 उम्मीदवारों को चुना गया और नियुक्त किया गया। शिकायतों के समाधान के लिए जोनल–लेवल कमेटी, स्टेट–लेवल कमेटी और एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई थी।

बिहार 30 सितंबर तक 30 से ज्यादा मिनरल ब्लॉक की नीलामी करेगा– सीएम सम्राट चौधरी

पटना, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को महत्वपूर्ण और रणनीतिक मिनरल ब्लॉक की नीलामी और भारत सरकार के कोयला और खान मंत्रालय द्वारा नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट (एनएमईडीटी) के संबंध में आयोजित एक वर्कशॉप का उद्घाटन किया।भारतीय राजनीति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि बिहार ने अपने मिनरल ब्लॉक का अध्ययन किया है और इस बात पर जोर दिया कि राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हुए संसाधनों का इस्तेमाल जनहित में किया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और समृद्ध बिहार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बिहार के 44 माइनिंग ब्लॉक में से 28 में सर्वे का काम आगे बढ़ चुका है और राज्य 30 सितंबर तक 30 से ज्यादा ब्लॉक के लिए प्रक्रिया पूरी करने का इरादा रखता है। माइनिंग गतिविधियां 15 अक्टूबर से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

कई मिनरल ब्लॉक पहले ही टेंडर के लिए रखे जा चुके हैं, जबकि अतिरिक्त ब्लॉक के लिए प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों को बाकी काम नौ महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। राज्य की मिनरल संपदा पर प्रकाश डालते हुए चौधरी ने रोहतास में लाइमस्टोन, औरंगाबाद में मिनरल संसाधन, जहानाबाद और जमुई में भंडार और गया, बांका और भागलपुर में अतिरिक्त संभावनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन संसाधनों का इस्तेमाल व्यवस्थित रूप से बिहार के लोगों के हित में किया जाएगा ।

तेजस्वी यादव की सरकार से मांग, पटना में दशरथ मांझी की मूर्ति और आश्रम बनाया जाए

पटना, (एजेंसी)। पटना में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यालय में माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 19वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, कई राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दलित और महादलित समुदायों के कई लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद, तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से मांग की कि वह पटना में दशरथ मांझी की मूर्ति लगाए और उनके नाम पर एक आश्रम बनाए। स्ततवत सवंकपदह के. उन्होंने बिहार में कथित भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। कथित डस्टबिन घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि कई अन्य मामलों में भी गड़बड़ियां सामने आई हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

देश के समस्त नामी गुमनामी, आजादी के दीवानों, अमर शहीदों को नमन करते हुए आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 2026 एवं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

विजय प्रकाश श्रीवास्तव
अधिवक्ता, सिविल कोर्ट,
(विधिक सलाहकार
देश की उपासना समाचार पत्र)
पता-जमैथा ,जौनपुर, उत्तर प्रदेश
सम्पर्क सूत्र 9450619319

उम्मीद खो चुके 301 चेहरों पर लौटी मुस्कान, जीआरपी ने लौटाए 55 लाख के मोबाइल

(दीपक श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ लखनऊ)

लखनऊ। मोबाइल खोने के बाद उसे दोबारा पाने की उम्मीद छोड़ चुके 301 लोगों के चेहरे उस समय खिल उठे, जब जीआरपी लखनऊ ने उनके खोए हुए मोबाइल फोन तलाशकर उन्हें वापस सौंप दिए। जीआरपी की इस पहल ने न सिर्फ लोगों की खुशी लौटाई, बल्कि पुलिस के प्रति भरोसा भी मजबूत किया। जीआरपी लखनऊ ने अलग–अलग स्थानों से बरामद 301 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपये बताई गई है। 18 अगस्त को जीआरपी पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल उनके मालिकों के सुपुर्द किए गए। मोबाइल

गुम होने के बाद पीड़ितों ने जीआरपी थानों और जनसुनवाई के दौरान अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं। पुलिस अधीक्षक जीआरपी लखनऊ रोहित मिश्रा ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सर्विलांस टीम और संबंधित थानों की पुलिस टीमों को मोबाइल तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी।टीमों ने लगातार तकनीकी निगरानी और प्रयासों के जरिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही अन्य राज्यों से भी मोबाइल फोन बरामद किए। इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए।खोया मोबाइल हाथ में आते ही किसी की आंखों में खुशी दिखी तो किसी के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौट आई। कई लोगों ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनका मोबाइल कभी वापस मिलेगा, लेकिन जीआरपी के प्रयासों से उनकी उम्मीद सच साबित हुई।मोबाइल पाने वाले लोगों ने जीआरपी टीम का आभार जताते हुए कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई ने उनके लिए खोई हुई उम्मीद वापस लौटा दी। जीआरपी के मुताबिक बरामद मोबाइल विभिन्न कंपनियों के मल्टीमीडिया फोन हैं। 301 मोबाइल की वापसी महज बरामदगी नहीं, बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास की मजबूत होती कड़ी की तस्वीर है।

संपादकीय

युवा, सुधार और विकसित भारत

स्वतंत्रता दिवस पर मोदी का फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया भाषण लाल किले से उनका लगातार 13वां भाषण, जो किसी भी गैर–कांग्रेसी प्रधानमंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है बड़े लक्ष्यों वाला और जाने–पहचाने अंदाज वाला था। विकसित भारत/2047 के लिए युवा शक्तिष थीम पर आधारित इस भाषण में शक्ति की सप्त धारा का ऐलान किया गया। यह सात बिंदुओं वाला एक ढांचा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, खेती, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ग्रीन–एंड–ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर शामिल हैं। इसमें सुधार की नई लहर के लिए पौराणिक सप्त सिंध‍ु का जिक्र किया गया। इसमें ठोस बातें युवाओं पर केंद्रित थीं एक करोड़ युवा भारतीयों के लिए मुफ्त एआई ट्रेनिंग, सेमीकंडक्टर मिशन जिसके तहत सात–आठ साल में और ज्यादा फैब्रिकेशन प्लांट लगाने का वादा किया गया, 2036 ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए 5 से 15 साल के बच्चों के लिए देशव्यापी स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग। एनर्जी के मामले में, मोदी ने बताया कि पहले प्रतिबंधित लगभग सभी ऑफशोर ब्लॉक खोज के लिए खोल दिए गए हैं, साथ ही रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन और हाइड्रोजन ट्रेनों पर भी प्रगति हुई है। औपचारिक तौर पर, आजादी के बाद पहली बार लाल किले पर पूरा वंदे मातरम् गाया गया जो इसकी 150वीं सालगिरह का प्रतीक था। भाषण में एक बात जो हद से ज्यादा आगे बढ़ गई, वह थी दिमागी नक्सलियों के बारे में चेतावनी कृ मोदी ने कहा कि ऐसे लोग माओवादी सोच रखते हैं और सत्ता के गलियारों में मौजूद हैं, जिनमें सरकारी पैनलों के सलाहकार भी शामिल हैं और उन्होंने ऐसे लोगों की पहचान करने और उन्हें अलग–थलग करने का आह्वान किया। उन्होंने इस शब्द को परिभाषित नहीं किया, और इस अस्पष्टता का कुछ ही घंटों में हथियार की तरह इस्तेमाल किया गयारू बीजेपी प्रवक्ताओं ने इसे सीध‍े राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर लागू किया, जिन्होंने लगातार दूसरे साल लाल किले के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। विचार धारा के प्रति सतर्कता का संकेत देने वाला एक वाक्यांश व्यक्तिगत राजनीतिक हमले में बदल गया कृ यह एक ऐसे भाषण के लिए बहुत ज्यादा था जिसका मकसद नाम लेकर विरोधियों को निशाना बनाने के बजाय एकजुट करना था। इससे भी बड़ी अति महत्वाकांक्षा थी, जो रास्ते में सुधार की जगह ले रही थी। यह भाषण मॉनसून सत्र के बेकार जाने के दो दिन बाद आया, जिसमें संसद में छात्रों के असंतोष, परीक्षा–पेपर लीक या युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर शायद ही कोई बहस हुई हो। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जून में 15–29 साल के भारतीयों के बीच बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 16.2 प्रतिशत रही, जबकि युवाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी एक साल में 42.7 प्रतिशत से घटकर 40.3 प्रतिशत हो गई। इस माहौल में, आलोचकों ने युवाओं पर केंद्रित इस ब्रांडिंग को सिर्फ रीपैकेजिंग (पुरानी चीज को नए रूप में पेश करना) माना। विपक्ष का विरोध तीन स्तरों पर हुआ। कांग्रेस ने भाषण को खोखला बताया– महाराष्ट्र यूनिट के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने मोदी के पिछले बारह भाषणों में किए गए वादों का हिसाब मांगा। जयराम रमेश ने दिमागी नक्सल शब्द को श्हताशाश का सबूत बताया यह पुराने अर्बन नक्सल टैग से आगे की बात थी। इन बातों से सरकार के सही दावों पर कोई असर नहीं पड़ता कृ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

संसद का मानसून सत्र जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा

आदित्य

संसद का मॉनसून सत्र जनता संसद का मॉनसून सत्र इस बात का साफ उदाहरण था कि संसदीय सत्र कैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। जिस तरह से यह सत्र खत्म हुआकृबिना स्पीकर के धन्यवाद भाषण केकृउससे ऐसा लगा कि सत्ता पक्ष कार्यवाही को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए उत्सुक था। सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ, उसी दिन जब छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रबंधन के विरोध में संसद भवन तक मार्च करने का फैसला किया था। उनके साथ जिस बेरहमी से पेश आया गया, उससे सरकार की छवि खराब ही हुई। वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने आतंकवादी नहीं थे, बल्कि उन सरकारी एजेंसियों के खिलाफ विरोध कर रहे छात्र थे जो उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही थीं, जैसा कि नीट परीक्षा रद्द होने से साफ हो गया था। पुलिस की कार्रवाई न केवल बर्बर थी, बल्कि नकाब पहने अज्ञात कर्मियों की मौजूदगी और छात्रों की बुरी तरह पिटाई ने इसे और भी परेशान करने वाला बना दिया। खबरों के अनुसार, कुछ पुलिसकर्मियों ने नेमप्लेट नहीं पहनी थी, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया, और घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह से स्पष्टीकरण की मांग की जानी चाहिए थी, जो संसद में अपने आक्रामक हस्तक्षेप और विपक्ष को चुप कराने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। फिर भी, उन्होंने संसद की कार्यवाही में शामिल न होने का फैसला किया, जबकि वे संसद परिसर में अपने कार्यालय में नियमित रूप से आते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सदन के बाहर विपक्ष पर हमला करने में मुखर रहते हैं, ने भी दूर रहना ही बेहतर समझा। अगर उनकी अनुपस्थिति से यह धारणा बनी कि वे नाराज विपक्ष का सामना करने को तैयार नहीं थे, तो इसके लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं। सरकार भले ही इस बात से संतुष्ट हो कि संसद की 19 दिनों की बैठक के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए, लेकिन यह आंकड़ा एक गंभीर विफलता को छिपाता है। परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा को छोड़कर, अन्य 11 विधेयक बिना किसी बहस या चर्चा के ही पारित कर दिए गए। संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, और कानूनों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी कितनी अच्छी तरह से जांच–परख की गई है। अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए विधेयकों की सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा जांच, उन पर सवाल और उन्हें बेहतर बनाने के लिए चर्चा की जानी चाहिए। वे संरचनात्मक खामियों और अनपेक्षित परिणामों की पहचान कर सकते हैं। जब ऐसी चर्चा नहीं होती है, तो पर्याप्त सार्वजनिक जांच के बिना कानूनों के लागू होने का खतरा बढ़ जाता है। जो कानून ठीक से तैयार किए जाते हैं, जिन पर बहस होती है और जिनमें संशोधन किए जाते हैं, उनके समय की कसौटी पर खरा उतरने की संभावना अधिक होती है। यह कोई संयोग नहीं है कि पुराने दंड संहिता बहुत कम संशोधनों के साथ लंबे समय तक कायम रहे। हालांकि, विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। कामकाज में बाधा डालना जांच–परख का विकल्प नहीं हो सकता। उनका फर्ज था कि वे 12 बिलों की जाँच करें, अगर उनमें कोई खतरनाक प्रावधान हों तो उन्हें सामने लाएँ और सुधार के सुझाव दें। संसदीय बहुमत का मतलब कानून बनाने में जल्दबाजी करने की छूट नहीं है। और न ही संसदीय विपक्ष का मतलब लगातार कामकाज में रुकावट डालना है। दोनों पक्षों की देश के प्रति यह जिम्मेदारी है कि संसद ठीक से काम करे। मॉनसून सत्र इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा और जिन लोगों को आज लोकतांत्रिक शासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

चुनावी पात्रता और नागरिकता के बीच बढ़ता विवाद

संजय

चुनावी अधिकारों और नागरिकता के बीच उलझा मुद्दा बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के एक साल बाद, यह बड़ा काम – जिसे बाद में कई दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बढ़ाया गया – डॉक्यूमेंटेशन, वोटर का नाम हटाने, वोटिंग का अधिकार छिनने और खुद नागरिकता के कानूनी मतलब को लेकर कई चिंताएं पैदा कर चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नागरिकता तय करना इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और SIR का मकसद मुख्य रूप से डुप्लीकेट और मृत वोटरों के नाम हटाना है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर वोटिंग का अध‍िकार तय करने का आधार नागरिकता है, तो कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक कैसे बनता है? संविधान और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता के नियम काफी सरल हैं और यह साफ करते हैं कि कौन भारतीय है। नागरिकता पाने के चार मुख्य तरीके हैंरू देश की सीमा में जन्म, नागरिक माता–पिता से जन्म (वंश), नेचुरलाइजेशन (प्राकृतिक रूप से नागरिकता) और रजिस्ट्रेशन। इनके अलावा, सीएए 2019 अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ध‍ार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नेचुरलाइजेशन/रजिस्ट्रेशन का एक खास तरीका बनाता है। ज्यादातर लोग जन्म से नागरिकता पाते हैं, जो तार्किक भी है क्योंकि ज्यादातर लोग नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिक नहीं बनते। यह बात न सिर्फ भारत के लिए, बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी सच है। अमेरिका की तरह, भारत में भी 1955 और 1986 के बीच जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती थी। 1986 में इसमें बदलाव किया गया ताकि जन्म से नागरिकता पाने के लिए माता–पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी हो जाए। 2003 में नियम में और बदलाव किया गया ताकि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा हुए किसी ऐसे व्यक्ति को नागरिकता न मिले जिसके माता–पिता में से कोई अवैध प्रवासी हो। भारत में ऐतिहासिक रूप से डॉक्यूमेंटेशन की कमी और जन्म के आधार पर नागरिकता के अध‍िकार में कटौती को देखते हुए, इसका मतलब है कि कई लोगों के लिए नागरिकता का दस्तावेजी सबूत जुटाना एक मुश्किल काम है। बस इतना कहना काफी है कि भारत के सभी नागरिकों के पास जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है। जन्म के अधिकार से मिलने वाली पक्की नागरिकता को धीरे–ध‍ीरे खत्म करने का मतलब है कि समय के साथ दस्तावेजी सबूतों पर निर्भरता बढ़ी है, जो वैसे भी भारत में कम ही रहे हैं। सभी नागरिकों के पास जाति प्रमाण पत्र, जमीन के रिकॉर्ड, स्ष्ठ प्रमाण पत्र या सरकारी नौकरी के दस्तावेज नहीं होते। इन सबका मतलब यह है कि अगर मान ली गई नागरिकता पर सवाल उठाया जाए और सबूत पेश करने की जिम्मेदारी नागरिकों पर हो, तो नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों की कमी से लाखों लोगों के वोटिंग अधिकारों पर असर पड़ सकता है। बिहार में 47 लाख और बंगाल में 91 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, इनमें से 27 लाख लोग हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाए क्योंकि उनके वोटिंग अधिकारों पर कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। बिहार और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर नोटिस जारी करने और नाम हटाने की वजह से यह चिंता पैदा हुई कि एसआईआर भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन जैसा ही है। इससे कानूनी जिम्मेदारी का आधार बदल गया है पहले नागरिक होने को मान लिया जाता

था, लेकिन अब दस्तावेजों के जरिए अपनी वैधता साबित करने की लगातार जरूरत पड़ती है। दस्तावेजों से जुड़ी सख्त शर्तों के कारण संबंधित अधिकारियों को गड़बड़ियों और तार्किक विसंगतियों को सुलझाना होगा। वोटिंग के लिए पात्रता तय करने में कई तरह की शर्तें और पेचीदगियाँ जोड़ी गई हैं, जिससे एक ऐसी उलझन पैदा हो गई है जिसे सुलझाना मुश्किल है और यह समझना भी कठिन है कि क्या हो रहा है और क्यों। 12 राज्यों मेंएसआईआर के दूसरे चरण में, वोटर लिस्ट से लगभग 7. 2 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब तक किसी की नागरिकता नहीं छीनी गई है, लेकिन कौन जानता है कि आगे क्या होगा। मई में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को एक वैध प्रक्रिया मानते हुए यह स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग यह तय करता है कि कौन वोट दे सकता है, लेकिन यह नहीं कि कौन नागरिक है। यह एक अच्छा भरोसा है, लेकिन इससे लाखों भारतीयों–खासकर गरीब, कम पढ़े–लिखे और अनपढ़ लोगोंकृकी चिंता कम नहीं होती। उन्हें नहीं पता कि 2026 के एसआईआर के बाद अगर वोटर लिस्ट से उनके नाम हटा दिए गए तो क्या होगा। तो, क्या एसआईआर पहली चेतावनी है? और आगे क्या इंतजार कर रहा है? ट्रिब्यूनल, जिनके सामने कई मामलों में सबूत पेश करना मुश्किल होता है? ऐसे हालात में क्या होगा? ये मुश्किल सवाल लाखों नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, जिनका हमेशा से मानना था कि उनकी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकताकृखासकर आधार, पैन कार्ड और डिजिटल पेमेंट के दौर में। लेकिन जब कोई राज्य अपने नागरिकों से नागरिकता साबित करने को कहता है, तो अमीरों की तुलना में गरीबों के फेल होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए नहीं कि वे नागरिक नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने कागजात ठीक से नहीं बनवाए होते। दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी–पटरी वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्रवासी और छोटे–मोटे काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे कम नागरिक हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी नागरिकता का कानूनी मतलब नहीं समझा और उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन उन्हें इसे साबित करने के लिए कहा जाएगा। प्रक्रिया से जुड़ी दिक्कतों के अलावा, एसआईआर प्रक्रिया के मानवीय पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वोटर लिस्ट से नाम कटने के डर और चिंता के साथ–साथ बुजुर्गों और दिहाड़ी मजदूरों को होने वाली परेशानियां जमीनी स्तर पर मौजूद मुश्किलों को उजागर करती हैं। मौजूदा वोटरों से अपनी पात्रता फिर से साबित करने के लिए कहकर, एसआईआर वोटर लिस्ट से जुड़ी नागरिकता की धारणा और प्रक्रिया की जटिलता के कारण लोगों के बाहर हो जाने की संभावना पर सवाल खड़े करता है। एसआईआर के खिलाफ सबसे बड़ी दलील संवैधानिक चिंता से जुड़ी है।

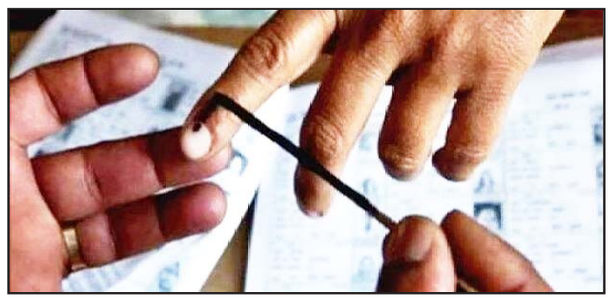

एल्गोरिदम के दौर में मानसिक स्वास्थ्य

विनोद

मानसिक स्वास्थ्य अक्षिता पांडे और डॉ. मैत्रेयी दास द्वारा कंपनियां एआई के फायदों जैसे ज्यादा कुशलता, कम गलतियां और डेटा–आधारित सटीकताकृपर तो जोर देती हैं, लेकिन एक जरूरी और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले पहलू पर ध्यान नहीं देतीं, वह है काम करने वालों की मानसिक सेहत परएआई को लागू करने का असर। एल्गोरिदम के शासन में जीवन और काम के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए तेजी से शोध हो रहे हैं। इस चर्चा में एक अहम योगदान 2024 में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कम्युनिकेशंस में प्रकाशित ब्युंग–जिक किम और जुलाक ली का शोध–पत्र है। दक्षिण कोरिया के 418 पेशेवरों (जो देश की सबसे ज्यादा तकनीकी रूप से उन्नत आबादी का हिस्सा हैं) के सर्वेक्षण पर आधारित यह शोध कार्यस्थल परएआई अपनाने से कर्मचारियों के तनाव, बर्नआउट (काम के कारण अत्यधिक थकान और मानसिक तनाव) और मनोवैज्ञानिक सेहत पर पड़ने वाले असर की जांच करता है। एल्गोरिदम का अदृश्य बोझ यह अध‍्ययन एक मनोवैज्ञानिक श्डोमिनो प्रभावश (एक घटना से दूसरी घटना का सिलसिला शुरू होना) को उजागर करता है एआई अपनाने से सीधे तौर पर बर्नआउट नहीं होता, लेकिन इससे नौकरी का तनाव बहुत बढ़ जाता है, जो बाद में बर्नआउट का एक बड़ा कारण बन जाता है। यह एक सूक्ष्म बदलाव है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। कर्मचारी जरूरी नहीं कि एआई के अस्तित्व से ही नाराज हों। बल्कि, एआई उन पर जो दबाव डालता है जैसे बदलाव की तेज गति, लगातार नई चीजें सीखने की जरूरत, और नौकरी के बेकार हो जाने या खत्म हो जाने का डरकृवही इस बढ़ती चिंता को हवा देता है। एआई टेक्नो–स्ट्रेस (तकनीक से जुड़ा तनाव) का माहौल बनाता है यह कई तरह के तनावों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यापक शब्द है, जिसमें शामिल हैं टेक्नो– ओवरलोड नए डिजिटल कामों और डिवाइस को संभालने की मजबूरी से परेशान होना टेक्नो–इनसिक्योरिटी यह डर कि ऑटोमेशन (स्वचालन) से नौकरी चली जाएगी टेक्नो–कॉम्प्लेक्सिटी एआई सिस्टम को तेजी से सीखने और उसके अनुसार ढलने में कठिनाई होना टेक्नो– अनसर्टेनिटी एआई सिस्टम के तहत काम के नतीजों या उम्मीदों को लेकर अनिश्चितता। इस दबाव की भारी मनोवैज्ञानिक कीमत चुकानी पड़ती है। जो काम पहले इंसानी समझ और रचनात्मकता पर निर्भर करते थे, वे अब अक्सर एल्गोरिदम द्वारा तय होते हैं। इससे कर्मचारियों को लगता है कि उनकी आजादी कम हो गई है और वे उस सिस्टम का ही एक हिस्सा बनकर रह गए हैं जिसमें वे काम करते हैं। इस बदलाव के कारण भावनात्मक थकान, काम से जुड़ाव की कमी और लाचारी की भावना बढ़ रही हैकृयह पैटर्न फाइनेंस और शिक्षा से लेकर हेल्थकेयर तक, सभी उद्योगों में देखा जा रहा है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किम और ली अपने निष्कर्ष तीन मुख्य मनोवैज्ञानिक मॉडलों पर आधारित करते हैं, जॉब डिमांड्स–रिसोर्सेज मॉडल यह बताता है कि बर्नआउट तब होता है जब काम की मांगें (जैसे एआई के लिए नई स्किल्स सीखना) उपलब्ध संसाधनों (जैसे ट्रेनिंग, मदद या भावनात्मक मजबूती) से ज्यादा हो जाती हैं। लोग अपने शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संसाधनों को बचाकर रखने की कोशिश करते हैं। जब एआई इन संसाधनों को नुकसान पहुँचाता है, जैसे कि कर्मचारियों को बेकार या अक्षम महसूस कराकर, तो लोग तनाव और बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। ट्रांसेक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग अगर एआई को मौके के बजाय खतरे के तौर पर देखा जाए, और अगर निपटने की क्षमता (कोपिंग स्किल्स) कमजोर हो या मदद न मिले, तो नतीजा मनोवैज्ञानिक तनाव होता है। आसान शब्दों में कहें तो, सिर्फ एआई ही कर्मचारियों को नुकसान नहीं पहुँचाताय बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि एआई को कैसे लागू किया जाता है, कैसे नियंत्रित किया जाता है और संगठनात्मक माहौल में उसे कैसे समझा जाता है। डिजिटल सेल्फ–एफिकेसी (आत्म–क्षमता) एक और अहम बात एआई सीखने की सेल्फ–एफिकेसी है, या आसान शब्दों में, एआई में महारत हासिल करने और उसका इस्तेमाल करने की व्यक्ति की क्षमता पर उसका भरोसा। ऐसे कर्मचारी तकनीकी बदलावों का सामना करते समय कम तनाव महसूस करते हैं और ज्यादा मजबूती से उनका सामना करते हैं। कम सेल्फ–एफिकेसी से लाचारी, चिंता और बर्नआउट जैसी समस्याएं होती हैं। इस संदर्भ में, सेल्फ–एफिकेसी कार्यस्थल पर एक नए तरह के सुरक्षा कवच का काम करती है। यह न केवल कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है, बल्कि उन्हें एआई–आधारित काम के माहौल में भावनात्मक रूप से निपटने के लिए भी तैयार करती है। बर्नआउट का नया रूप पुराने समय में, बर्नआउट का संबंध लंबे समय तक काम करने, खराब मैनेजमेंट, अवास्तविक उम्मीदों और भावनात्मक रूप से मुश्किल कामों से जोड़ा जाता था। हालाँकि, एल्गोरिदम के दौर में, बर्नआउट एक नया और ज्यादा अदृश्य रूप ले रहा है, जो न केवल ज्यादा काम करने से, बल्कि अलगाव, अध‍िकारहीनता और लगातार डिजिटल ओवरलोड से भी जुड़ा है। आज, एल्गोरिदम तय करते हैं कि हम कैसे काम करते हैं, बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं और यहाँ तक कि आराम भी कैसे करते हैं। नोटिफिकेशन निजी और पेशेवर जिंदगी के बीच की सीमा को धुंध‍ला कर देते हैं, जबकि प्रोडक्टिविटी पर केंद्रित डिजिटल कल्चर हमेशा उपलब्ध, जवाबदेह और कुशल रहने का दबाव बनाते हैं। साथ ही, एल्गोरिदम सिस्टम परफॉर्मेंस की निगरानी करके, व्यवहार का अनुमान लगाकर और रूटीन तय करके आजादी को कम करते हैं, जिससे लोगों को लग सकता है कि उन्हें बदला जा सकता है और वे अपने काम से भावनात्मक रूप से दूर हो रहे हैं। इसका नतीजा एक ऐसे बर्नआउट के रूप में सामने आता है जो सिर्फ शारीरिक थकान के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक थकान, भावनात्मक सुन्नता और कभी भी पूरी तरह से ऑफलाइन न हो पाने की लगातार बनी रहने वाली भावना के बारे में है। एल्गोरिदम के दौर में, बर्नआउट (काम का अत्यध‍िक तनाव) एक नया और कम दिखने वाला रूप ले रहा है। यह सिर्फ ज्यादा काम करने से ही नहीं, बल्कि अलगाव, अधिकारहीनता और लगातार डिजिटल ओवरलोड (बहुत ज्यादा डिजिटल जानकारी या काम का बोझ) से भी पैदा होता है। कर्मचारी अक्सर बताते हैं कि वे एआई सिस्टम की वजह से खुद को अलग–थलग महसूस करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम बिना इंसानी दखल के फैसले लेते हैं। कुछ लोग परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, प्रोडक्टिविटी ट्रैकर्स और एल्गोरिदम–आधारित मूल्यांकन के जरिए लगातार निगरानी में रहने का एहसास भी बताते हैंय ये सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम से लेकर काम की क्षमता तक हर चीज पर नजर रखते हैं। लगातार निगरानी का यह कल्चर कर्मचारियों को हर समय खुद पर नजर रखने (सेल्फ–मॉनिटरिंग) के लिए मजबूर करता है, जिससे हर पल प्रोडक्टिव दिखने का दबाव बढ़ जाता है। समय के साथ, इससे एंग्जायटी (चिंता), भावनात्मक थकान और काम की जगह पर खुद के नियंत्रण या फैसले लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है। इस तरह का बर्नआउट कम साफ तौर पर दिखता है, लेकिन यह कम नुकसानदायक नहीं है। यह आत्मविश्वास कम कर सकता है, काम से गैर–हाजिरी बढ़ा सकता है, और बहुत गंभीर मामलों में डिप्रेशन या नौकरी छोड़ने की नौबत भी ला सकता है। क्या किया जा सकता है एआई अपनाने की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सपोर्ट को सामान्य बनाएं, संगठनों को यह समझना होगा कि एआई लागू करना सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक बदलाव भी है। इसके लिए कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता, नियमित बातचीत (चेक–इन) और अपनी चिंता या उलझन जाहिर करने के लिए सुरक्षित माहौल देना जरूरी है। सभी स्तरों पर डिजिटल क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाएं, डिजिटल आत्मविश्वास विकसित करने के लिए लगातार ट्रेनिंग, मेंटरिंग और साथियों से मिलने वाले सपोर्ट की जरूरत है। मकसद सिर्फ तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि भावनात्मक मजबूती भी है। सहानुभूति को ध्यान में रखकर एआई को फिर से डिजाइन करें। एआई सिस्टम बनाते समय यूजर की अपनी मर्जी और नियंत्रण (यूजर एजेंसी) को केंद्र में रखना चाहिए।

अपनापन की शांत शक्ति

रवि

शांत शक्ति लीडरशिप की चर्चाओं में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने (एट्रिशन) के बारे में सवाल आम हो गए हैं। संगठन यह समझने में बहुत निवेश करते हैं कि प्रतिभाशाली लोग क्यों नौकरी छोड़ते हैं और उन्हें रोकने के लिए क्या करना चाहिए। हाल ही में ऐसी ही एक बातचीत के दौरान, मैंने चार दशक से भी पहले रेलवे में अपने करियर की शुरुआत के समय के एक बहुत अलग वर्कप्लेस कल्चर के बारे में सोचा। शुरुआती दो हफ्तों तक मेंटेनेंस शेड के रोजाना के दौरों में एक सीनियर अफसर मेरे साथ होते थे। दो हफ्ते बाद, उन्होंने बस इतना कहा, ष्सोमवार से, आप अकेले काम संभालेंगे।ष शेड और उसके स्टाफ की जिम्मेदारी अब मेरी थी। फिर भी, मैं कभी अकेला नहीं था। जब भी मुश्किल मामले सामने आतेकृ चाहे ट्रेड यूनियन से जुड़े हों या हेडक्वार्टर सेकृमुझे पता था कि सीनियर अफसर मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। रेलवे में मेरे पूरे कार्यकाल के दौरान यह कल्चर बना रहा। सीनियर अफसरों ने मुश्किल फैसलों में मेरा साथ दिया, बिना बेइज्जत किए गलतियाँ सुध‍ारीं और मुझे आत्मविश्वास के साथ नई जिम्मेदारियाँ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इन अनुभवों ने मुझे अपनापन महसूस कराया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि इन छोटी–छोटी बातों ने मुझ पर उस समय के मुकाबले कहीं ज्यादा असर डाला था। मैंने पाया कि मैं भी अपने से जूनियर साथियों को वैसा ही सहयोग दे रहा था, इसलिए नहीं कि किसी ने मुझसे ऐसा करने को कहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने कभी मेरे लिए भी ऐसा ही किया था। जब मैं लगभग पच्चीस साल बाद प्राइवेट सेक्टर में आया, तो वर्कप्लेस काफी बदल चुका था। करियर ज्यादा मोबाइल हो गए थे, संगठन ज्यादा डायनामिक हो गए थे और रीस्ट्रक्चरिंग आम हो गई थी। इन बदलावों से कई फायदे हुएकृबेहतर अवसर, तेजी से विकास और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। मुझे महसूस हुआ कि कुछ ऐसी चीजकृ जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण हैकृउसे बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा थारू खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़े होने का एहसास। कई एम्प्लॉयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इंसेंटिव और रिटेंशन स्ट्रैटेजी बनाने में काफी संसाधन लगाते हैं। हर संगठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन वे कभी–कभी मानवीय व्यवहार की छोटी–छोटी बातों के असर को कम आंकते हैंकृजैसे उत्साह बढ़ाने वाली बातचीत, सोच–समझकर दी गई सलाह, सच्ची तारीफ या किसी सीनियर का किसी के विकास में दिलचस्पी लेना। ऐसे पल कुछ ऐसा बनाते हैं जो सिर्फ पॉलिसी से नहीं बन सकतारू संगठन के साथ एक स्थायी भावनात्मक जुड़ाव। अपनापन ऑर्गनाइजेशनल चार्ट या एम्प्लॉई हैंडबुक के जरिए थोपा नहीं जा सकता। यह तब विकसित होता है जब लोगों को लगता है कि वे अपनी भूमिका से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो कर्मचारी इस जुड़ाव को महसूस करते हैं, वे अक्सर अनुबंध के तहत अपेक्षित योगदान से कहीं ज्यादा योगदान देने को तैयार रहते हैं क्योंकि वे संगठन के उद्देश्य को अपना उद्देश्य मानने लगते हैं। शायद मर्जर और एक्विजिशन के दौरान यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग लाइन और सिस्टम को काफी तेजी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। भरोसा, पहचान और अपनापन – ये चीजें अपने–आप नहीं बनतीं। जब बदलाव का दौर हो और लोग खुद को नजरअंदाज महसूस करें, तो अक्सर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में यह बात दिखने से बहुत पहले ही लोगों का काम के प्रति लगाव कमजोर पड़ जाता है। इन अनुभवों ने मुझे एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए प्रेरित किया। ऐसी दुनिया में जहाँ करियर तेजी से बदलते रहते हैं और पेशेवर रिश्ते पहले के मुकाबले कम समय के होते हैं, वहाँ संगठनों को कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ–साथ अपनापन पैदा करने पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। टेक्नोलॉजी काम को तेज बना सकती है। इंसेंटिव्स से परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। लेकिन अक्सर कोई दूसरा इंसान ही यह तय करता है कि कोई व्यक्ति किसी संगठन के लिए सिर्फ काम कर रहा है या सच में उसका हिस्सा महसूस करता है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि मेरे साथ जो चीजें हमेशा के लिए रह गईं, वे कोई पॉलिसी, प्रमोशन या कोई खास उपलब्धि नहीं थीं। बल्कि वह भरोसा था जो दूसरों ने मुझ पर जतायाकृ अक्सर बिना कहे ही। शायद लोग इसी बात को सबसे लंबे समय तक याद रखते हैंकृउन्हें मिली सलाह नहीं, बल्कि उन पर जताया गया भरोसा और यह एहसास कि उन्हें महत्व दिया गया। संगठन बदलते हैं, करियर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे अनुभव इस बात को आकार देते रहते हैं कि लोग कैसे नेतृत्व करते हैं, काम करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं।

पीयू में मनायी गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। मंगलवार को को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) द्वारा कुलपति प्रो. वंदना सिंह के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक डॉ. शशिकांत यादव ने रोवर्स–रेंजर्स परिसर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नेताजी के जीवन, संघर्ष, अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति को स्मरण करते हुए कहा कि नेताजी का जीवन देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने

कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने अदम्य साहस और नेतृत्व से देशवासियों में स्वाधीनता की भावना को प्रबल किया। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और राष्ट्र के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है। इस अवसर पर उत्कर्ष सिंह, आर्यन, संतोष, मुन्ना रावत सहित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। सभी ने नेताजी के आदर्शों को आत्मसात करने और राष्ट्रहित में कार्य करने का संकल्प लिया। ?

मीलाद–उन–नबी की तैयारियों को लेकर डीएम को सौंपा 11 सूत्रीय मांग पत्र

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में आगामी 26 अगस्त को पैगंबर हजरत मोहम्मद के यौमे पैदाइश के अवसर पर आयोजित होने वाले ईद–मीलादुन्नबी के जुलूस और जलसे की तैयारियों को लेकर मरकजी सीरत कमेटी ने मंगलवार को जिलाधिकारी को संबोधित 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। कमेटी ने ऐतिहासिक जुलूस और जलसे को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने की मांग की। कमेटी ने मांग की कि शाही ईदगाह से शाही अटाला मस्जिद तक जुलूस के पारंपरिक मार्ग को गड्ढामुक्त कराया जाए। साथ ही 27 अगस्त तक

शहर को रात्रिकालीन विद्युत कटौती से मुक्त रखने और 26 अगस्त को विशेष रूप से 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध ा किया गया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने को देखते हुए कमेटी ने जुलूस मार्ग पर दो एंबुलेंस और दो मेडिकल कैंप लगाने की मांग की। इसके अलावा एक अग्निशमन वाहन की तैनाती और 26 अगस्त को चार पानी के टैंकर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। स्वच्छता व्यवस्था के तहत जुलूस के मुख्य मार्गों की विशेष साफ–सफाई और चूना छिड़काव कराने, दो मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करने तथा शहर के सभी डीलक्स शौचालयों को 26 अगस्त की रातभर निरूशुल्क खुला रखने की मांग की गई। कमेटी ने नगर पालिका परिषद के मैदान को साफ–सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था के साथ रातभर खुला रखने का भी अनुरोध किया। वहीं, जुलूस और जलसे के दौरान कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए पिछले वर्षों की तरह पर्याप्त संख्या में पुलिस और पीएसी बल की तैनाती की मांग की गई। कमेटी ने पुलिस अधीक्षक को कानून–व्यवस्था और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को साफ–सफाई से संबंधित अलग–अलग ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर सदर ओबैदा शिराजी, जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद रज्जू, हसीन बबलू सभासद, अरशद कुरैशी, मौलाना अनवार कासमी, जफर मसूद, फिरोज अंसार खान, कन्वीनर फिरोज अहमद पप्पू, खजांची मो. फराज खान, फरहान शेख, अबु हुजैफा खान, मो. सादिक, मो. आमिर, मीडिया प्रभारी रियाजुल हक, नुरुद्दीन मंसूरी अधिवक्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

यूपी में बनेंगे दो सुपर हाईवे, एनएचएएआइ ने तैयार किया 7000 करोड़ का मास्टर प्लान

लखनऊ, संवाददाता। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएएआइ) द्वारा कानपुर–कबरई होते हुए भोपाल और पानीपत–शामली–गोरखपुर होते हुए सिलीगुड़ी तक बनाए जाने वाले हाईवे सफर के दौरान एक्सप्रेसवे का अहसास कराएंगे। दोनों हाईवे पर सफर के दौरान बीच में कोई व्यवधान नहीं आएगा। एक्सप्रेसवे की तर्ज पर ये दोनों हाईवे पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड (प्रवेश नियंत्रित) होंगे। सिर्फ निर्धारित प्रवेश और निकास बिंदु से ही वाहन आ–जा सकेंगे। एनएचएआइ के क्षेत्रीय अधि ाकारी गौतम विशाल के मुताबिक कानपुर–कबरई तथा पानीपत –गोरखपुर –कुशीनगर तक प्रस्तावित हाईवे पूरी तरह प्रवेश नियंत्रित होंगे। तय स्थान से ही वाहन पर आ–जा सकेंगे। बीच रास्ते में कहीं से कोई वाहन या जानवर हाईवे पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इससे न सिर्फ दुर्घटनाएं कम होंगी अपितु वाहन बिना किसी व्यवधान के निर्धारित सीमा 100 किमी तक प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। उन्होंने बताया है कि 117.7 किमी लंबे कानपुर–कबरई हाईवे का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए टेंडर इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हो जाएगा। पानीपत–शामली–गोरखपुर–सिलीगुड़ी हाईवे में यूपी में शामली से कुशीनगर तक लगभग 745 किमी. राजमार्ग के निर्माण कार्य का टेंडर अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत होगा। कानपुर से कबरई तक एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे (आर्थिक गलियारा) की लंबाई 117.7 किमी होगी। कानपुर से शुरू होकर यह हाईवे कानपुर देहात, हमीरपुर, (कबरई) महोबा होते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर, सागर, विदिशा होते हुए भोपाल को जोड़ेगा। यूपी में कानपुर से कबरई तक के खंड के निर्माण पर 7145.14 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है। एक जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने कानपुर–कबरई हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी थी।

नागपंचमी पर निकली साष्टांग दंडवत यात्रा शिव भक्त जमीन पर लेटकर जाते हुए भक्त

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में पवित्र श्रावण मास और नागपंचमी के अवसर पर सोमवार को बोल बम दंडवत संघ जौनपुर की ओर से भव्य साष्टांग दंडवत यात्रा निकाली गई। हनुमान घाट स्थित आदि गंगा गोमती के तट से हजारों शिवभक्तों ने पवित्र जल लेकर यात्रा शुरू की। इस दौरान पूरे नगर में 'हर–हर महादेव' के जयघोष गूंजते रहे। यात्रा हनुमान घाट से शुरू होकर चहारसू चौराहा, कोतवाली चौराहा और नवाब यूसुफ रोड होते हुए मोहल्ला आलमगंज स्थित श्री श्री 1008 बाबा जागेश्वर नाथ धाम पहुंची। श्रद्धालुओं ने साष्टांग दंडवत करते हुए बाबा के दरबार तक पहुंचकर जलाभिषेक किया। यात्रा में बाबा जागेश्वर नाथ का रथ शोभायात्रा के रूप में आगे चल रहा था। गाजे–बाजे और भक्ति गीतों के बीच शिवभक्त हर–हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। इससे पूरा नगर शिवमय नजर आया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायण केसरी 'नंदी बम' ने बताया कि इस धार्मिक आयोजन में हर वर्ष बड़ी संख्या में शिवभक्त शामिल होते हैं।ये यात्रा 18 वर्षों से निकाली जा रही है।जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा का जलाभिषेक करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने सभी सहयोगियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए शिवभक्तों से धार्मिक आयोजनों में श्रद्धा और अनुशासन के साथ शामिल होने की अपील की। वही संबंध में बाबा जागेश्वर नाथ के महंथ अंबुजानंद महाराज ने बताया कि बाबा का यह शिवलिंग लगभग 100 वर्ष पुराना है यहां जो भी भक्त है सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं जिला अभिषेक करते है उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए साथ ही दंडवत यात्रा के गुजरने वाले रास्ते को पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया है जहां रेड कार्पेट पर सिर्फ कवरिया ही लेट कर बाबा जागेश्वर नाथ को जलाभिषेक करने जा रहे हैं।

उचित दर विक्रेताओं का लाभांश 90 से बढ़कर 125 रुपये प्रति क्विंटल,मुख्यमंत्री ने की घोषणा, जौनपुर में हुआ सजीव प्रसारण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। नई व्यवस्था का शुभारंभ सोमवार को लोकभवन, लखनऊ से किया गया। इसका उद्देश्य उचित दर विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सोमवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जौनपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों सहित कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में सजीव प्रसारण किया गया। कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह, नगर पालिका परिषद जौनपुर की अध्यक्ष मनोरमा मौर्या और जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उचित दर विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री के उद्बोधन और लाभांश वृद्धि की घोषणा का सजीव प्रसारण देखा। इस अवसर पर विध ान परिषद सदस्य बृजेश सिंह ने कहा कि उचित दर विक्रेता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न को पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी और सुचारु रूप से पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला पूर्ति अधिकारी ने खाद्य एवं रसद विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा उचित दर विक्रेताओं के हित में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम में मौजूद उचित दर विक्रेताओं ने लाभांश बढ़ाए जाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से संचालित करने में प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यक्रम का समापन उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं उचित दर विक्रेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया गया।वही दूसरी तरफ जौनपुर कोटेदार संघ के कार्यकारी अध्यक्ष दया शंकर निगम ने मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि हम लोगों की माग काफी दिनों से थी मुख्यमंत्री जी ने ये तोहफा देकर हम सभी का सम्मान किया है हमारे परिवारों का ध्यान रखा है इसके लिय हम सभी उनके आभारी रहेंगे।

किड्स बैकर्स में शॉर्ट सर्किट से आग, 10 लाख का सामान जलकर राख

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में पुलिस लाइन के सामने स्थित किड्स बैकर्स में मंगलवार दोपहर करीब 12रू30 बजे शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से बेकरी में रखा करीब 10 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार ने दुकान में रखे अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने का प्रयास किया साथ ही फायर ब्रिडेग को जानकारी दिया सूचना मिलते मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बेकरी के मालिक जगदंबा प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक बिजली का तार जलकर नीचे गिरा, जिससे आग लग गई। उस समय बेकरी में तीन लोग मौजूद थे। उन्होंने तत्काल आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बेकरी में प्लास्टिक का सामान अधिक होने के कारण आग तेजी से फैल गई। कर्मचारियों के प्रयास के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। दुकानदार का कहना है कि यदि फायर ब्रिगेड की टीम और जल्दी पहुंच जाती तो नुकसान को कम किया जा सकता था। वही इस मामले में जानकारी देते हुए सीएफओ आरपी राय ने बताया कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आ रहा है। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है।

अब एक ही एनसीएमसी से पूरे देश की मेट्रो और बसों में कर सकेंगे सफर

लखनऊ, संवाददाता। मेट्रो में गो स्मार्ट कार्ड से सफर करने वाले यात्री उसे बदलकर निशुल्क नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) ले सकेंगे। लखनऊ मेट्रो ने अपने सभी स्टेशनों पर सोमवार को एक्सचेंज विंडो खोल दिया है। यात्रियों को इन काउंटर पर 30 दिनों के भीतर पुराने कार्ड को जमा करके नया एनसीएमसी कार्ड लेना होगा। इस कार्ड को बदलने से पहले यात्रियों को उसके मौजूदा बैलेंस को खत्म करना होगा। लखनऊ मेट्रो में एक महीने के बाद पुराने कार्ड मान्य नहीं होंगे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक नार्थ –साउथ कारिडोर पर प्रतिदिन लगभग 89 हजार यात्री सफर करते हैं। लखनऊ मेट्रो ने डेढ़ लाख गो स्मार्ट कार्ड बनाए हैं। इसमें से 85 हजार गो स्मार्ट कार्ड सक्रिय हैं। इस बीच 21 जुलाई को यूपीएमआरसी ने एनसीएमसी को लांच कर दिया है। इस कार्ड का उपयोग देश की अन्य मेट्रो, बसों, पार्किंग और रिटेल सेवाओं में भी किया जा सकता है। इसके लिए दूसरे शहरों में भी यात्रा के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मौजूदा कार्ड की व्यवस्था की तरह ही लखनऊ मेट्रो में हर यात्रा पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। गो स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध पूरी शेष राशि पहले उपयोग करने के बाद मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर इसका सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के बाद यात्री को सरेंडर रसीद प्रदान की जाएगी। इसके पश्चात यात्री को अपना पुराना गो स्मार्ट कार्ड और सरेंडर रसीद स्टेशन पर स्थित एयरटेल पेमेंट्स बैंक कियास्क पर जमा करना होगा। मोबाइल फोन पर ओटीपी सत्यापन के बाद यात्री को नया एनसीएमसी निःशुल्क जारी किया जाएगा।

'ददरौल क्षेत्र में डॉ रामरहीस वर्मा के अस्पताल की हो रही सराहना,समर्पित सेवा और बेहतर इलाज से मरीजों में जीता विश्वास'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहाँपुर' जनपद के विकास खंड ददरौल क्षेत्र ग्राम भरगवां में संचालित वर्मा अस्पताल ने क्षेत्र के ग्रामीण एवं समीपवर्ती इलाकों के मरीजों के लिए वर्मा अस्पताल बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बन चुका है। वर्मा अस्पताल की ख्याति चारों ओर फैली हुई है। यहाँ पर दूर दराज से मरीज आकर स्वास्थ्य सेवाओं का भरपूर लाभ ले रहे हैं। अपनी सटीक चिकित्सीय देखरेख,अनुभव और सौम्य व्यवहार के बल पर डॉ वर्मा ने न केवल मरीजों को राहत दिलाई है,बल्कि क्षेत्र में एक विश्वसनीय चिकित्सक के रूप में अपनी खास पहचान भी बनाई है। अस्पताल में आने वाले हर छोटे–बड़े मरीज को प्राथमिकता दी जाती है। डॉ वर्मा मरीजों की की समस्याओं को

धैयपूर्वक सुनते हैं,जिससे मरीज आध ा रोग तो बातचीत के दौरान ही भूल जाता है। डॉ वर्मा ने बताया कि हमारे अस्पताल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाना है। यहां बिना किसी अनावश्यक आर्थिक बोझ के सटीक जांच और दवाइयां दी जाती हैं। अस्पताल परिसर में साफ –सफाई और मरीजों के बैठने की समुचित व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता है,जिससे मरीजों और उनके परिजनों को सहज अनुभव होता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक,किसी भी आपात स्थिति में डॉ वर्मा की त्वरित प्रतिक्रिया और सही मार्गदर्शन से मरीजों को समय पर राहत मिली है। डॉ रामरहीस वर्मा की सेवा भावना ने क्षेत्र में एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि डॉ रामरहीस वर्मा एक कुशल चिकित्सक के साथ –साथ उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी अग्रणी भूमिका में पहचान बनाई है। डॉ वर्मा वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य के रूप में भी लोगों के दुःख दर्द को समझकर उनकी समस्याओं के निराकरण कराने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

उचित दर विक्रेताओं का लाभांश 90 से 125 हुआ मुख्यमंत्री ने की घोषणा, जौनपुर में हुआ सजीव प्रसारण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था का शुभारंभ लोकभवन, लखनऊ से किया गया, जिसका उद्देश्य प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। सोमवार को 12 बजे से 2 बजे तक इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जौनपुर जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों और कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में भी किया गया। कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह 'प्रिंशु', नगर पालिका परिषद जौनपुर की अध्यक्ष मनोरमा मौर्या और जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. उपस्थित रहे।उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उचित दर विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री के उद्बोधन और लाभांश वृद्धि की घोषणा का सजीव प्रसारण देखा। अतिथियों ने शासन के इस निर्णय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उचित दर विक्रेताओं को विस्तृत जानकारी प्रदान की। विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह 'प्रिंशु' ने इस अवसर पर कहा कि उचित दर विक्रेता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न को पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी और सुचारु रूप से पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जिला पूर्ति अधि ाकारी ने खाद्य एवं रसद विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं और उचित दर विक्रेताओं के हित में किए जा रहे सरकारी प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। उपस्थित उचित दर विक्रेताओं ने लाभांश वृद्धि के इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु रूप से संचालित करने में प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यक्रम का समापन उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उचित दर विक्रेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया गया।

सावन सोमवार और नागपंचमी पर त्रिलोचन महादेव मंदिर, और गौरी शंकर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर प्राचीन त्रिलोचन महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर से पहले ही बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। मंदिर परिसर हर–हर महादेव और बम–बम भोले के जयघोष से गूंजता रहा। मुख्य पुजारी रविशंकर गिरी उर्फ सोनू ने बताया कि रात्रि आरती के बाद करीब 2रू30 बजे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। मंदिर प्रशासन के अनुसार, सुबह 10 बजे तक करीब 30 हजार श्रद्धालु बाबा त्रिलोचन महादेव के दर्शन कर चुके थे। भक्त कतारबद्ध होकर जलाभिषेक और पूजन–अर्चन करते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और मालाएं अर्पित कर विधिवत पूजा की। नागपंचमी के अवसर पर नाग देवता के प्रतीक स्वरूप विशेष पूजन भी किया गया। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के चलते मंदिर के बाहर करीब 200 मीटर लंबी कतार लग गई। इसमें महिला, पुरुष और बुजुर्ग श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। दिनभर भंडारे में लोगों की आवाजाही बनी रही। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर, मेला क्षेत्र और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। महिला पुलिस, सिविल पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहे। स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग की टीमें भी मुस्तैद रहीं। प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र विक्रम सिंह पुलिस बल के साथ मेला क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। इसी तरह सुजानगंज के गौरीशंकर धाम में भी सावन के तीसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां करीब 500 मीटर लंबी दो कतारें लगी रहीं। 14वीं शताब्दी (भर शासनकाल) से जुड़ा एक अति प्राचीन और ऐतिहासिक शक्तिपीठ है, जहां अर्धनारीश्वर रूप में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है और इसे क्षेत्र में असीम आस्था व चमत्कारिक केंद्र माना जाता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं बल्कि प्रगट (स्वयंभू) और शाश्वत है। यह शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त अर्धनारीश्वर रूप का दिव्य दर्शन कराता है। ऐसी मान्यता है कि 14वीं सदी में एक चरवाहे ने देखा कि एक विशेष टीले पर गाय के थनों से दूध अपने आप उस काले पत्थर पर गिर रहा है, जिसके बाद खुदाई न करवाकर वहाँ मंदिर की स्थापना की गई। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार, आरती के समय यहाँ बजने वाले घंटे की ध्वनि जितनी दूर तक (लगभग 5 किमी) जाती है, उतनी परिधि में कोई भीषण प्राकृतिक आपदा नहीं आती। श्रावण मास के सोमवारों और महाशिवरात्रि पर यहाँ जौनपुर के अलावा प्रतापगढ़ व प्रयागराज से भारी संख्या में कांवरिया आकर जलाभिषेक करते हैं। प्रत्येक शनिवार और सोमवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती है और मेल का आयोजन होता है। मंदिर परिसर के पास पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं को सुचारु रूप से दर्शन कराने की व्यवस्था की। राजस्व कर्मियों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद रही।

गोवंश संरक्षण के लिए 'गो निधि' मुहिम शुरू, क्यूआर कोड से करें सहयोग – महापौर

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।गोवंश संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए अयोध्या नगर निगम ने 'गो निधि' अभियान की शुरुआत की।जोनल कार्यालय में आयोजित समारोह में महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार के साथ अभियान का शुभारंभ किया।इस दौरान क्यूआर कोड के माध्यम से यहां पार्षद एवं अन्य लोगों ने गोवंश संरक्षण के लिए सहयोग राशि जमा की।महापौर ने कहा कि गोवंश संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। 'गो निधि' अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को इस पुनीत कार्य से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्यूआर कोड के माध्यम से नागरिक अपनी इच्छानुसार सहयोग राशि दे सकेंगे।उन्होंने कहा कि वह इसके लिए समाज के समक्ष वर्ग से संपर्क करेंगे। इस अवसर पर उपसभापति संतोष सिंह, अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, भारत भार्गव, सुमित कुमार, पार्षद विनय जायसवाल, अनिल सिंह, रमाशंकर निषाद, अनिकेत त्रिपाठी, रिशु पांडे, महेंद्र शुक्ला सहित नगर निगम के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

जिले मे आपराधिक घटनाओं मे बढोत्तरी से पुलिस कार्य शैली पर लग रहा प्रश्न चिन्ह

अयोध्या।रामनगरी अयोध्या में एक ओर देश–विदेश से श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले के कोतवाली नगर सहित अलग–अलग थाना क्षेत्रों में घटित लूट, छिनैती, चोरी, हत्या, फायरिंग, मारपीट और अन्य आपराधिक घटनाओं मे बढ़ोतरी हुई है।जिसके चलते पुलिस कार्यशैली पर सवालिया निशान खडा हो रहा है।देखा जाए तो इधर अगस्त महीने में ही कोतवाली नगर के अलावा अन्य थाना क्षेत्र में अपराधी घटनाएं हुई है। जिसमें कुछ का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और बाकी में एक ही रटा रटाया जवाब रहता है कि विवेचना जारी है। इससे पहले भी कई अपराधी घटनाएं जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई है जिसका खुलासा अभी पुलिस नहीं कर सकी है।कोतवाली नगर के अलावा थाना कैंट, कोतवाली अयोध्या, थाना राम जन्मभूमि, थाना गोसाईगंज, थाना महाराजगंज,कोतवाली बीकापुर, थाना पूरा कलंदर,थाना हैदरगंज,थाना इनायत नगर,कुमारगंज,थाना खंडासा, थाना पटरंगा, थाना मवई, थाना रुदौली सहित अधिकतर थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक घटनाएं हुई है जिसमें पुलिस इसमें शामिल कुछ आरोपी को पकड़ कर शेष मामला ठंडा बस्ते में डालकर क्या बताने का प्रयास करती है कि विवेचना चल रही है और अपराधी शीघ्र गिरफ्तार होंगे।अभी कुछ दिन पहले महाराजगंज थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना,थाना पूरा कलंदर में जान से मारने की कोशिश, पिछले दिनों तारुन क्षेत्र के घूरी टीकर गांव जमीन विवाद के दौरान दबंगो द्वारा पुलिस टीम पर हमला,थाना तारुन क्षेत्र मे चोरी की घटनाओ मे बढोत्तरी, पूरा कलंदर थाना क्षेत्र मे छिनैती की घटनाओं के अलावा कई थानों में अपराधी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है।जो बाजारों, प्रमुख मार्गों, सुनसान इलाकों, धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर संबंधित सीओ, प्रभारी निरीक्षक ध्यानाध्यक्ष व नियमित पेट्रोलिंग तथा प्रभावी बीट कर्मियों पर सवालिया निशान खड़ी कर रही है।

देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का अयोध्या रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत

अयोध्या।भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे का भव्य स्वागत अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट पं कृपा निधान तिवारी साथ में चाणक्य परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद तिवारी आफत पूर्व प्रधान राम भरत पांडे अश्वनी तिवारी श्रीकांत पाठक गोपाल तिवारी प्रदीप पाठक जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू सरकार से नामित पार्षद बबलू मिश्र आदि ने फूल माला व अंग वस्त्र सौंप कर भगवान श्री राम जन्म भूमि अयोध्या धाम की पावन धरती पर भव्य स्वागत किया। स्वागत से अवीभूत पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार से चलकर रेल मार्ग अयोध्या धाम में राम लला के दर्शन हेतु आए हैं।अयोध्या धाम में सपरिवार पधारे पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जन्मभूमि में रामलला का और श्री बजरंगबली का दर्शन करने का कार्यक्रम है वह रात्रि विश्राम अयोध्या धाम के रानो पाली स्थित उदासीन आश्रम के गेस्ट हाउस में रुकेंगे पूरे देश में ब्राह्मणों की आवाज बुलंद करने वाले श्री चौबे बिहार के अकेले ऐसे नेता हैं जो अपने समाज के साथ सर्व समाज का हमेशा ध्यान रखते हैं और सबके लिए कंधे से कंधा मिलाकर हर विपरीत परिस्थिति में खड़े मिलते हैं अयोध्या धाम में उनकी यात्रा के कई निहितार्थ निकाले जा रहे हैं वह देश के विश्व ब्राह्मण समाज को एकजुट करके 6 बिंदुओं पर चलाए जा रहे देशव्यापी ब्राह्मण समाज के आंदोलन को धार देने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं जिसके चलते पूरे देश में ब्राह्मण समाज के बड़े नेता स्थापित नेता के रूप में उनका काफी प्रभाव माना जा रहा है।

स्वतंत्रता दिवस पर रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया ।

देश की उपासना समाचार पत्र

मुम्बई ब्यूरो चीफ धनन्जय विश्वकर्मा। मुंबई के दहिसर पूर्व से एक ऐसी खबर सामने आई है, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति के साथ–साथ मानव सेवा का अनूठा संदेश देखने को मिला। दहिसर पूर्व के रावलपाड़ा स्थित साई मंदिर हॉल में श्री विश्वकर्मा चौरिटेबल ट्रस्ट एवं विश्वकर्मा समाज की ओर से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। खास बात यह है कि यह सेवा अभियान लगातार पिछले पांच वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया। आयोजन स्थल पर रक्तदाताओं के लिए आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था भी मौजूद रही। वहीं, इस सामाजिक एवं जनसेवा के कार्यक्रम में विधायक प्रकाश दादा सुर्वे भी पहुंचे। उन्होंने रक्तदान करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाया और रामा विश्वकर्मा तथा विश्वकर्मा समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। रामा विश्वकर्मा की पहल से आयोजित यह रक्तदान अभियान न सिर्फ मानव सेवा का संदेश देता है, बल्कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'देशभक्ति के साथ समाजसेवा' की मिसाल भी पेश करता है। आयोजकों का संदेश साफ है । एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचा सकता है। इसलिए रक्तदान करें और मानवता की इस मुहिम में अपना योगदान दें।

खस्ताहाल सड़क बनी हादसों का सबब,बड़े–बड़े गड्ढे दे रहे दुर्घटना को दावत

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। शहर के कैंट थाना क्षेत्र में गौरा पट्टी वाली गली से नियावां चौराहे तक जाने वाली सड़क इन दिनों बदहाली का शिकार है।सड़क पर जगह–जगह बने बड़े–बड़े गड्ढे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के चलते आए दिन हादसे का खतरा बना रहता है और कई बार ई–रिक्शा के पलटने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।स्थानीय लोगों के मुताबिक, पूरी सड़क खराब नहीं है, बल्कि गौरा पट्टी वाली गली से लेकर नियावां चौराहे तक का कुछ हिस्सा बेहद जर्जर स्थिति में पहुंच गया है।इस छोटे से हिस्से में जगह–जगह गहरे गड्ढे होने के कारण दोपहिया वाहन चालकों को विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।रात के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि गड्ढे स्पष्ट दिखाई नहीं देते और वाहन चालक अचानक संतुलन खो सकते हैं।लोगों का आरोप है कि सड़क की खराब स्थिति को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित विभाग को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बने गड्ढे लगातार दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करता नजर आ रहा है।सबसे अधिक परेशानी ई–रिक्शा, बाइक और पैदल आने–जाने वाले लोगों को होती है। गड्ढों से बचने के प्रयास में वाहन चालक अचानक दिशा बदलते हैं, जिससे सामने से आने वाले वाहनों से टक्कर का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो किसी दिन यहां गंभीर दुर्घटना हो सकती है।क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग और नगर प्रशासन से मांग की है कि गौरा पट्टी वाली गली से नियावां चौराहे तक खराब सड़क का तत्काल निरीक्षण कराकर गड्ढों को भरवाया जाए और सड़क की आवश्यक मरम्मत कराई जाए, ताकि राहगीरों और वाहन चालकों को राहत मिल सके तथा किसी संभावित बड़े हादसे को टाला जा सके।अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे के बाद जागेगा या उससे पहले ही सड़क की मरम्मत कराकर लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराएगा

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 24 अगस्त तक

अयोध्या।मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण सुषमा निषाद ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 से संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत मध्याकार आर0ए0एस0 में 3 यूनिट (सामान्य वर्ग) एवं रियरिंग यूनिट के निर्माण 22.667 हेक्ट (महिला एवं अनुसूचित जाति), बैकयार्ड आर0ए0एस0 241 यूनिट (महिला वर्ग) जलाशय में मत्स्य अगुलिका संचय 65000 अंगुलिका (सामान्य, महिला एवं अनुसमचित जाति), एवं 500 यूनिट पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिये आजीविका और पोषण सम्बन्धी सहायता परियोजनाओं हेतु उपलब्ध अवशेष लक्ष्य के सापेक्ष योजना के लाभ से जनसामान्य को आच्छादित करने के लिये ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय पोर्टल 14 अगस्त से खोला गया है। आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनाँक 24.08.2026 है।योजनान्तर्गत परियोजना का विवरण, इकाई लागत, आवेदन करने की प्रकिया आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख व विस्तृत विवरण को विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उक्त योजनाओं में यदि भविष्य में कोई संशोधन होता है तो संशोधित प्राविधान लागू होंगे। योजना में पूर्व के वर्षों में निरस्तध्रतिक्षारत आवेदन वाले आवेदक पुनः आवेदन कर सकते है। उक्त से सम्बन्धित समस्त जानकारी जनपदीय कार्यालय मत्स्य विभाग अयोध्या से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है।

जीआरपी ने क्यूआरटी टीम के साथ अयोध्या धाम पर चलाया सघन चेकिंग अभियान

अयोध्या।सोमवार देर शाम सावन पर्व के दौरान अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को लेकर प्रभारी निरीक्षक कैंट रेलवे स्टेशन अनिल प्रकाश सिंह ने सघन चेकिंग अभियान चलाया।उन्होंने चौकी प्रभारी अयोध्या धाम जयंत दूबे के साथ रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम के प्लेटफार्म,सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट काउंटर और यात्री प्रतीक्षालय सहित विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग किया।इस मौके पर उन्होंने चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ यात्रियों और उनके सामान पर नजर रखते हुए स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।इस मौके पर उन्होंने बताया कि सावन मेले को लेकर कावड़ यात्रियों तथा श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो इस दौरान कोई भी संदिग्ध व्यक्ति किसी तरह की आरक्षाक्त न फैला सके इसके लिए यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी यह चेकिंग अभियान निरंतर चलाया जाएगा। बताया कि चेकिंग के दौरान कोई संदिग्ध व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं मिली और स्थिति सामान्य एवं शांतिपूर्ण रही।चेकिंग अभियान में कांस्टेबल विजय सिंह, प्रशांत सिंह के अलावा अन्य जीआरपी कर्मी तथा क्यूआरटी टीम के मनजीत सिंह शामिल रहे।

मूलधन जमा कराएं, ब्याज से पाएं मुक्ति, नगर निगम ने शुरू की ओटीएस योजना

(डॉक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।गृहकर और जलकर के बकायेदारों को राहत देने के लिए नगर निगम अयोध्या ने वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू कर दी है। योजना के तहत बकायेदारों को केवल मूलधन जमा करना होगा। मूलधन पर अब तक लगा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। योजना के पहले ही दिन 12 बकायेदारों ने आवेदन कर इस योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में जिन भवन स्वामियों पर गृहकर अथवा जलकर बकाया है, वे ओटीएस योजना के तहत अपना बकाया निस्तारित करा सकते हैं। मूलधन जमा किए जाने पर उस पर देय ब्याज को माफ करने का प्रावधान किया गया है। इससे लंबे समय से बकाया कर वाले नागरिकों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।योजना के शुभारंभ के पहले दिन नगर निगम सभागार में अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार और जोनल अधिकारी सुभाष त्रिपाठी की मौजूदगी में बकायेदारों से आवेदन लिए गए। अधिकारियों ने आवेदकों के प्रपत्रों की जांच कर उनका निस्तारण कराया और योजना की प्रक्रिया की जानकारी दी।गजेंद्र कुमार ने बताया कि ओटीएस योजना से एक ओर जहां करदाताओं को बकाया ब्याज से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नगर निगम के लंबित राजस्व की वसूली में तेजी आएगी। उन्होंने बकायेदारों से अपील की कि योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए समय रहते आवेदन करें और मूलधन जमा कर अपने बकाये का निस्तारण कराएं।

चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दिए जाने पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद,भगवान जरूर देंगे सजा

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।एसआईटी टीम ने राम मंदिर चढावा मामले मे चंपत राय तथा डॉ अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया है इसका विरोध करते हुए फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह करोडो श्रद्धालुओ की आस्था के साथ छल हुआ है। जिसे भगवान कभी नहीं माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही इन लोगों को बचा ले, शलेकिन यह प्रभु श्रीराम के दरबार की चोरी है।सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है और इससे अयोध्या की छवि कलंकित हुई है।उन्होंने कहा कि वे लगातार सदन में इस मुद्दे को उठाया और प्रधानमंत्री से भी जांच को लेकर अपेक्षा की। धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब–जब धर्म की हानि होती है, कोई न कोई शक्ति सामने आती है।साथ ही साथ दावा किया कि जिम्मेदार लोग बचेंगे नहीं और समय आने पर उन्हें सजा मिलेगी।वही अंबेडकरनगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की माता के निधन पर अवधेश प्रसाद ने दुख जताया।उन्होंने कहा कि मृतका ने उन्हें दो बार आशीर्वाद दिया था और अपने हाथों से भोजन भी कराया था।मौत को लेकर पुलिस की ओर से हार्ट अटैक बताए जाने पर उन्होंने सवाल उठाए।अवधेश प्रसाद ने कहा कि उसके मुंह में कपड़े ठूँसे गए थे उसके आभूषण भी गायब हैं कहा कि घटना को तोड़–मरोड़कर पेश नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष जांच कर पूरे रहस्य का खुलासा होना चाहिए।अवधेश प्रसाद ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और इलाके में शांति का माहौल कायम करने की मांग की।

'मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में तहसील सवायजपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस हुआ आयोजित'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'सवायजपुर(हरदोई)' जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से तहसील सवायजपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल की अध्यक्षता में किया गया। सीडीओ ने समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाधान दिवस के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने फरियादियों से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन,राशन कार्ड, आवास आदि की जानकारी ली। उन्होंने पात्र लाभार्थियों से पूछा कि उन्हें पेंशन का लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। जिन पात्र व्यक्तियों को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था, उनके प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करते हुए शीघ्र पेंशन का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

सीडीओ ने फरियादियों से आयुष्मान कार्ड के संबंध में भी जानकारी ली। जिन पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे, उनके आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि समाधान दिवस में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। जिन प्रकरणों का निस्तारण मौके पर संभव है, उन्हें तत्काल निस्तारित किया जाए तथा जिन मामलों में स्थलीय जांच अथवा अन्य विभागों से समन्वय की आवश्यकता है, उनमें निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। अधिकारी एवं कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ आमजन की समस्याओं को सुनें और पात्र लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी शिवानी सिंह,तहसीलदार विनोद कुमार, विकास खंड अधिकारी संबंधित विभागों के अधिकारी,कर्मचारी सहित अन्य तहसील स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में आए 14 प्रार्थना पत्र, 10 शिकायतों का मौके पर महापौर ने किया निस्तारण

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में नागरिकों की 14 शिकायतें प्राप्त हुईं, इनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही महापौर ने निस्तारण कर दिया।शेष शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।जनसुनवाई की अध्यक्षता करते हुए महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने अधिकारियों को मौके पर जाकर नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु को देखते हुए शहर में कहीं भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए हर संभव उपाय किए जाएं। सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।

नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में सड़क व नाली निर्माण, जलभराव, पेयजल आपूर्ति, सीवर लाइन की खुदाई सहित अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई की गई।इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, भारत भार्गव, सुमित कुमार, सहायक नगर आयुक्त गुरु प्रसाद पांडे, जोनल अधिकारी विनय सिंह, महाप्रबंधक जलकर सौरभ श्रीवास्तव,मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राममणि शुक्ल,सहायक अभियंता निर्माण राजपति यादव, भारत वर्मा, सहायक अभियंता जलकर जयकुमार सहित नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

पोखरे में नहाने गए तीन बच्चों की मौत, इकलौता बेटा भी शामिल

गोरखपुर, संवाददाता। नाग पंचमी के पर्व पर बदौली बाबू गांव में उस समय मातम पसर गया, जब पुतली पीटने की रस्म के बाद पोखरे में नहाने गए तीन बच्चे गहरे पानी में डूब गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में हरीश (11), सचिन (14) और अनुज (9) की मौत हुई है। बताया गया कि नाग पंचमी के अवसर पर गांव के बच्चे पोखरे के पास पुतली पीटने की रस्म में शामिल थे। इसी दौरान कुछ बच्चे पोखरे में नहाने लगे। नहाते समय तीन बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। बच्चों को डूबता देखकर मौके पर चीख–पुकार मच गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विकास सिंह बच्चों को बचाने के लिए पोखरे में उतर गए। उन्होंने ग्रामीणों के साथ काफी देर तक पानी में बच्चों की तलाश की। तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही तहसीलदार सुशील कुमार भारतीय, नायब तहसीलदार राकेश शुक्ला, सीईओ अनुज कुमार सिंह और कस्बा चौकी प्रभारी विकास सिंह भदौरिया समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।